One Day Online Interdisciplinary

NATIONAL CONFERENCE

on

COVID -19 PANDEMIC AND ITS IMPACT ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDIA

30th June 2020.

Organized by

Prin. Dr. Haridas Fere

Vasantrao Kale Mahavidyalaya, Dhoki,

Tq. & Dist. Osmanabad (MS)

Editor

Dr. B.V. Maind

(Convener)

Chief Editor

Dr. Haridas Fere

(Principal)

PATRON

Hon. Vikram Vasantrao Kale

(MLC, Maharatashta)

Secretary, Kisan Shikshan Prasarak Mandal,

Borgaon (Kale) Tq. & Dist. Latur.

ORGANIZING COMMITTEE

Dr. Haridas Fere (Principal)

Dr. B.V.Maind (Convenor)

Mr. D.D. Gaikwad (Asst. Prof.)

Mr. B.N. Deshmukh (Asst. Prof.)

Mr. J.A. Lokhande (Asso. Prof.)

Mr. R.V. Kamble (Asst. Prof.)

Dr. N.P. Manale (Asst. Prof.)

Mr. M.D. Shrimangale (Asst. Prof.)

Dr.Mrs. J.B. Nade (Asst. Prof.)

Dr. R.P. Jadhav (Asst. Prof.)

Dr. Pradeep Ingale (Phy. Director)

Mr. D.N. Sarde (Librarian)

Dr. J.S. Deshmukh (Asst. Prof.)

Mr. S.V. Jogdand (Asst. Prof.)

And all Teaching and Non-Teaching Staff of College

©The Principal, K.S.P.M.'S Vasantrao Kale Mahavidyalaya, Dhoki.

All rights reserved. No part of this publication can be reproduced, stored or transmitted in any form or by any Means, Electronic as Mechanical, including Photocopy, Micro-filming and recording or by any information Storage and retrieval System without the Proper Permission in writing of copyright owners. The opinions expressed in the articles by the Authors and contributors are their own and the Chief Editor assumes no responsibility for the same.

Disclaimer

Research papers published in this Special Issue are the intellectual contribution done by the authors. Authors are solely responsible for their published work in this special Issue and the Editor of this special Issue are not responsible in any form.

ISSN : 2349-638x

Special Issue No.76 Published by:

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)

Peer Review and Indexed Journal

Website : www.aiirjournal.com

Impact Factor 6.293

Chief Editor – Pramod P. Tandale

Sr.No.	Name Of Author	Title Of Paper	Page No.
36	डॉ. संदीप गोरख साळवे	उच्च शिक्षालेते समय छात्रों को आने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन	103
37	योगेश्वर साहू	आत्मनिर्भरता : भारत के पुनरुत्थान की योजना	106
38	डॉ.राजकुमार पंडितराव जाधव	कोविड-19 का भारतीय समाज पर पड़ा गहरा प्रभाव	112
39	प्राचार्य डॉ. हरिदास फेरे	कोवीड-19 महामारीचे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवरील महासंकट	114
40	प्रा.डॉ.डी. बी. तांदुळजेकर	करोणा विशाणू संकट आणि भारतीय अर्थव्यवस्था	119
41	प्रा. डॉ. गोवर्धन खेडकर	कोरोना विषाणू आणि लॉकडाऊन नंतरची भारतीय अर्थव्यवस्था	122
42	डॉ. अर्जुन मोहनराव मोरे	भारतीय कृषी व्यवस्थेवर (Covid 19) कोरोना व्हायरसचा परिणाम : एक अभ्यास	124
43	प्रा. डॉ. अविनाश विलासराव पवार	कोविड-19 चा भारतीय समाज जीवनावर परिणाम	129
44	प्रा.डॉ. अनंत नरवडे	कोविड-19 चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम	134
45	प्रा.डॉ. वी.व्ही. मैंद	आत्मनिर्भर भारत अभियानाची वैशिष्ट्ये	139
46	डॉ. मिनाक्षी भास्कर जाधव	जागतिक महामारीचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम	144
47	डॉ. बालाजी तुळशीराम घुटे	कोव्हीड-19 आणि पर्यावरणीय बदल	148
48	प्रा.डॉ. व्ही.डी. आचार्य	Covid 19 महामारी आणि सरकारची धोरणे : एक राजकीय अभ्यास	152
49	डॉ. शैलजा भारतराव बरूरे	कोरोना काळातील भारतीय सामाजिक वास्तव	156
50	प्रा. डॉ. क्षितिश्वर जी. ढोबळे	कोवीड – १९ महामारीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविष क्षेत्रावरील प्रभाव	159
51	प्रा.आनंद मुसळे	कोविड-19 आणि त्याचा सामाजिक परिणाम	162
52	प्रा.प्रदीप दाजीबा पाटील	कोविड-19 : वास्तव आणि अपेक्षा	167
53	प्रा.डॉ.सुदाम वसंतराव पवार	कोव्हीड-19 आणि शैक्षणिक क्षेत्र	172
54	डॉ.सुधाकर अच्युतराव सांगळे	लॉकडाऊनचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम	176

योगेश्वर साहू
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय डोंडी,
जिला-बालोद, छत्तीसगढ़
उच्च शिक्षा विभाग,छत्तीसगढ़ शासन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई, 2020 राष्ट्र को संबोधित किया। महामारी से जूझते हुए अपनी जान गंवा देने वाले लोगों को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण जो संकट उभर कर सामने आया है, वह अप्रत्याशित है, लेकिन इस लड़ाई में हमें न केवल अपनी रक्षा करने की जरूरत है, बल्कि निरंतर आगे भी बढ़ते रहना होगा। कोविड काल से पहले और बाद की दुनिया का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए। संकट को एक अवसर में बदलने की बात कहते हुए उन्होंने पीपीई किट और एन-95 मास्क का उदाहरण दिया, जिनका भारत में उत्पादन लगभग नगण्य से बढ़कर 2-2 लाख पीस प्रतिदिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमंडलीकृत दुनिया में आत्मनिर्भरता के मायने बदल गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो वह आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार के रूप में मानती है, और भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है।

प्रधानमंत्री के इस राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया और सुधार की साहसिक योजना की घोषणा भी की, जिसका लक्ष्य 21वीं सदी में भारत का पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान है। मोदी के कल्पनाशीलता भरे भाषण की खासियत यह थी कि उसमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का खाका खींचा गया था, जिससे भारत दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। अपने संबोधन में उन्होंने स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करने, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार करने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रांडों में बदलने की जरूरत पर खासा जोर दिया।

विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक नया अभियान "आत्मनिर्भर भारत अभियान" भी आरंभ किया।

आत्मनिर्भर भारत

आत्मनिर्भरता की व्याख्या करते हुए प्रधानमंत्री ने शास्त्रों से 'सर्वम् आत्मवशम् सुखम्' का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है कि "जो हमारे नियंत्रण में है वही सुख या प्रसन्नता है।" आज की वैश्विक परिस्थितियों में आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ बदल गया है। मानव केंद्रित वैश्वीकरण बनाम अर्थव्यवस्था केंद्रित वैश्वीकरण पर बहस जारी है। भारत का मूलभूत चिंतन दुनिया के लिए आशा की किरण बन रहा है। भारत की संस्कृति और परंपरा आत्मनिर्भरता की बात करती है और वसुधैव

कुटुंबकम इसकी आत्मा है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भारत को दुनिया से अलग करना नहीं है। भारत के लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्मकेंद्रित व्यवस्था नहीं है। भारत की आत्मनिर्भरता विश्व के सुख, सहयोग और विश्व शांति में निहित है। भारत विश्व के कल्याण में विश्वास करता है। यह वह संस्कृति है, जो विश्व कल्याण में विश्वास करती है, सभी जीवित प्राणियों की बात करती है और पूरे विश्व को परिवार मानती है। 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या' इस संस्कृति आधार है अर्थात यह पृथ्वी को मां मानती है। भारत की प्रगति दुनिया से जुड़ी है और जब भारत भूमि आत्मनिर्भर हो जाएगी तो यह विश्व की समृद्धि भी सुनिश्चित करेगी। भारत की प्रगति हमेशा दुनिया की प्रगति से जुड़ी रही है।

21वीं सदी को भारत की सदी बनाना जिम्मेदारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। यह हमारा सपना नहीं है बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। आत्मनिर्भरता ही भारत के लिए एकमात्र रास्ता है। विश्व की आज की स्थिति हमें बताती है कि आत्मनिर्भर भारत ही इकलौता रास्ता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है - "एषः पंथः यानी आत्मनिर्भर भारत" आत्मनिर्भरता वैश्वीकरण को मानव केंद्रित बनाएगी।आत्म निर्भर भारत सर्वोत्तम उत्पाद तैयार करेगा।"हम सर्वश्रेष्ठ उत्पाद बनाएंगे, अपनी गुणवत्ता में और भी सुधार करेंगे, आपूर्ति श्रृंखला को और भी आधुनिक बनाएंगे, हम ऐसा कर सकते हैं और निश्चित रूप से ऐसा करेंगे।"

आत्मनिर्भरता के पांच स्तंभ :-

- पहला स्तंभ अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जिसमें इन्क्रीमेंटल चैंज (लगातार बदलाव) के बजाय क्वांटम जंप (एकाएक बड़ा बदलाव) हो।
- दूसरा स्तंभ बुनियादी ढांचा है, ऐसा बुनियादी ढांचा जो आधुनिक भारत की पहचान बन गया है।
- तीसरा स्तंभ हमारी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था, जो 21वीं सदी के सपने पूरे करने वाली तकनीक से चलती हो; जो पिछली सदी की नीतियों पर आधारित नहीं हो।
- चौथा स्तंभ हमारी डेमोग्राफी (जनांकिकी) है, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी जीवंत डेमोग्राफी ही हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का सोत है।
- पांचवां स्तंभ मांग है, हमारी अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का चक्र वह ताकत है, जिसे पूरी क्षमता तक पहुंचाने की जरूरत है। देश में मांग बढ़ाने के लिए और इस मांग को पूरा करने के लिए हमारी आपूर्ति श्रृंखला के हरेक पक्ष को सशक्त बनाने की जरूरत है। हम अपनी मिट्टी की खुशबू और अपने मजदूरों के पसीने से बनी अपनी आपूर्ति श्रृंखला और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे।

घोषणाओं का सारांश : आत्मनिर्भर भारत अभियान

12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की (जोकि भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है)। इसका उद्देश्य विश्वव्यापी सप्लाई चेन्स की कड़ी प्रतिस्पर्धा में देश को आत्मनिर्भर बनाना और कोविड-19 से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, प्रवासियों को सशक्त करने में मदद करना है। इस घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पांच प्रेस वार्ताएं कीं और आर्थिक पैकेज के अंतर्गत विस्तृत उपायों की घोषणा की। इस नोट में आर्थिक पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य उपायों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

1.सरकारी नीतिगत सुधार : 2020-2021 के लिए राज्य सरकारों की कर्ज़ लेने की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% से बढ़ाकर 5% किया जाएगा। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होने का अनुमान है। जीएसडीपी के 3.5% तक की उधारी बिना शर्त होगी। नई पीएसई नीति की घोषणा की गई है जिसमें पीएसईज़ के निजीकरण की योजना है, कुछ रणनीतिक क्षेत्रों के उपक्रमों को छोड़कर। इन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक पीएसई रहेगा, लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी। भारतीय एमएसएमईज़ को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकारी खरीद संबंधी टैंडर्स में 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबर टैंडर को अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.व्यापार जगत के लिए उपाय (एमएसएमई सहित) : सभी व्यापार को तीन लाख करोड़ रुपए तक का कोलेट्रल मुक्त ऑटोमैटिक कर्ज़ दिया जाएगा। एमएसएमई बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से 29 फरवरी, 2020 तक अपने संपूर्ण बकाया ऋण का 20% तक उधार ले सकते हैं। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉरपस के साथ फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा। इससे एमएसएमई को विकास की संभावनाओं और वायबिलिटी के साथ इक्विटी फंडिंग मिलेगी। इस फंड स्ट्रक्चर से 50,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। इस योजना का लक्ष्य स्ट्रेस्ड एमएसएमई को सहयोग देना है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) से जूझ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमईज़ के प्रमोटर्स को बैंकों से ऋण दिया जाएगा जिससे एमएसएमईज़ को इक्विटी मिलेगी। एक विशेष लिक्विडिटी योजना की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत सरकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/हाउसिंग फाइनांस कंपनियों (एचएफसीज़)/लघु वित्त संस्थानों (एमएफआईज़) के इनवेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांजैक्शन में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्र सरकार इन सिक्योरिटीज़ में 100% की गारंटी देगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार मार्च, अप्रैल और मई में पात्र इस्टैबिलशमेंट्स के ईपीएफ खातों में नियोक्ता का 12% और कर्मचारी का 12% अंशदान चुकाएगी। यह अगले तीन महीने (जून, जुलाई और अगस्त) में जारी रहेगा। इससे व्यापार और कर्मचारियों को 2,500 करोड़ रुपए की राहत मिलने का अनुमान है। ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी इस्टैबलिशमेंट्स के लिए नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों के वैधानिक पीएफ अंशदान को 12% से घटाकर 10% किया जाएगा। यह योजना उन श्रमिकों पर लागू होगी, जोकि पीएम गरीब कल्याण पैकेज और उसके विस्तार के अंतर्गत 24% ईपीएफ सहायता के पात्र नहीं हैं। फुटपाथी दुकानदारों को आसान ऋण की सुविधा देने वाली एक विशेष योजना को एक महीने के भीतर शुरू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की शुरुआती कार्यशील पूंजी के लिए हर दुकानदार को बैंक ऋण दिया जाएगा।

3. कृषि और संबद्ध क्षेत्र : किसानों को किसान क्रेडिट काईस के जरिए रियायती दरों पर संस्थागत ऋण की सुविधा दी जाएगी। इस योजना में 2.5 करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रुपए की लागत से रियायती ऋण दिया जाएगा। फर्म गेट और एग्रेगेशन प्वाइंट्स (जैसे सहकारी संघों और किसान उत्पादक संगठनों) पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा। फार्म गेट एक ऐसा बाजार है जहां खरीदार किसानों से सीधा उत्पाद खरीद सकते

हैं। किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशाली पूंजी के रूप में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। यह राशि नाबार्ड के जरिए ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबीज़) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीज़) को अपने फसल ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) मरीन और इनलैंड फिशरीज़ के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए शुरू की जाएगी। डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, और पशु चारे से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड स्थापित किया जाएगा। जनजातियों/आदिवासियों के रोजगार सृजन हेतु कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी (कैंपा) के अंतर्गत सरकार 6,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी देगी।

आवश्यक वस्तु एक्ट, 1955 कुछ वस्तुओं के उत्पादन, सप्लाई और वितरण को नियंत्रित करता है ताकि देश में उन वस्तुओं की कमी न हो। एक्ट में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू सहित खाद्य पदार्थों को डीरेगुलेट करने के लिए संशोधन किया जाएगा। इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने से किसानों को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है।

4. प्रवासी श्रमिक : प्रवासी श्रमिक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना के अंतर्गत मार्च 2021 तक भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) का उपयोग कर सकेंगे। यह योजना प्रवासी मजदूरों के लिए राशन तक पहुंच की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी का परिचय देगी। प्रवासी श्रमिक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट राशन कार्ड या राज्य कार्ड के लाभार्थी नहीं, उन्हें दो महीने के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलो चना मिलेगा। इस योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके अंतर्गत आठ करोड़ प्रवासियों को लाभ मिलने का अनुमान है। प्रवासी श्रमिकों/शहरी निर्धनों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत सस्ते किराए पर आवास मुहैय्या कराए जाएंगे। यह लक्ष्य निम्नलिखित के जरिए हासिल किया जाएगा: (i) पीपीपी के जरिए शहरों में सरकारी फंडेड मकानों को एआरएचसीज़ में बदलना, और (ii) मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, उद्योगों, संस्थानों, संगठनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे अपनी निजी भूमि में एआरएचसीज़ को विकसित करें और उन्हें संचालित करें।

5. नागरिक उड्डयन : भारतीय एयरस्पेस के उपयोग पर लगे प्रतिबंधों को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक प्रभावशाली हो। इससे एयरस्पेस के इष्टतम उपयोग, ईंधन के उपयोग और समय में कमी, और उड्डयन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है। पीपीपी मॉडल के जरिए विश्वस्तरीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। पहले दौर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने नीलामी के जरिए छह में से तीन हवाई अड्डों (अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु) को पीपीपी आधार पर संचालित एवं उसका रखरखाव करने के लिए चुना है।

6. रक्षा : रक्षा क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट से मैन्यूफैक्चरिंग में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। देश को उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। हथियारों/प्लेटफार्मों की एक सूची जारी की जाएग

जिनका आयात एक निश्चित वर्ष के लिए प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के जरिए ऑर्डिनेंस सप्लाई में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करने की योजना बनाई है।

7. ऊर्जा : बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी प्रदान की जाएगी। ये पावर फाइनांस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के फंड के रूप में होंगे। कोयले की निकासी के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें खदानों से रेलवे साइडिंग तक कोयले के मशीनीकृत (कन्वेयर बेल्ट) हस्तांतरण में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।

डिस्कॉम की अक्षमताओं से उपभोक्ता प्रभावित नहीं होंगे। डिस्कॉम्स की सेवाओं के मानकों और संबद्ध सजा को स्पष्ट किया जाएगा ताकि कंपनियां पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करें और लोड-शेडिंग से बचें। बिजली क्षेत्र में रेगुलेटरी एसेट्स को समाप्त किया जाएगा। रेगुलेटरी एसेट अनुमत शुल्क बढ़ोतरी की स्थिति में डिस्कॉम्स से संबंधित एक फंड होता है। अस्थिरता से बचने के लिए इसे राजस्व में नहीं वसूला जाता क्योंकि इसे उपभोक्ताओं को हस्तांतरित नहीं किया जाता। डिस्कॉम्स को इस राशि को बाद के चरण में राज्य सरकार या अनुमत सरचार्ज के रूप में उपभोक्ताओं से प्राप्त करने की अनुमति है। अब तक विभिन्न राज्यों में रेगुलेटरी एसेट के रूप में काफी बड़ी पूंजी मौजूद है जिसे संबंधित राज्यों के डिस्कॉम्स लिक्विडिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभाग/यूटिलिटीज़ का निजीकरण होगा।

8. आवास : मध्यम आय वर्ग (वार्षिक आय 6 लाख रुपए और 18 लाख रुपए के बीच) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को मार्च 2021 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे आवास क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। कोविड 19 को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ द्वारा 'अप्रत्याशित घटना' के तौर पर माना जाएगा। व्यक्तिगत एप्लीकेशंस के बिना 25 मार्च, 2020 या उसके बाद समाप्त होने वाले सभी पंजीकृत प्रॉजेक्ट्स के पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीखों को छह महीने बढ़ाया जाएगा।

9. सामाजिक क्षेत्र : सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर के संस्थानों में निवेश किया जाएगा। महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए जिला और ब्लॉक स्तरों पर लैब नेटवर्क्स को मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगे। इससे मनरेगा के लिए केंद्रीय बजट आबंटन 61,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए (65% वृद्धि) हो गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की कुल लागत 81,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस के लिए पीएम-ई-विद्या को लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दीक्षा योजना (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा को सहयोग देने की सुविधाएं शामिल होंगी।

10. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुख्य कदम : जिस वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई, उसमें लिक्विडिटी जुटाने में सहयोग हेतु आरबीआई के कुछ कदम भी शामिल हैं। कैश रिज़र्व रेशो

करोड रुपए प्राप्त हुए। (सीआरआर) को कम किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1,37,000 करोड रुपए प्राप्त हुए। नॉन एनबीएफसीज़ और एमएफआई के, तथा अन्य इनवेस्टमेंट ग्रेडेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में निवेश हेतु कुल 1,50,050 करोड रुपए के टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (टीएलटीआरओ) की योजना बनाई गई। म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फेसिलिटी (एसएलएफ) की घोषणा की गई। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के लिए पॉलिटी रेपो रेट पर 50,000 करोड रुपए मूल्य की स्पेशनल रीफाइनांस फेसिलिटीज़ की घोषणा की गई। सभी प्रकार के ऋणों के लिए वर्किंग कैपिटल फेसिलिटीज़ की किश्तों और ब्याज के भुगतान पर तीन महीने का अधिस्थगन प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष

विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री उन लोगों से बहुत आगे निकल गए, जो अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन पैकेज भर की मांग कर रहे थे। उन्होंने नए भारत का खाका बताया है, जो लोकल भी होगा और ग्लोबल भी होगा। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण ही नया मंत्र होगा ।प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भरता सुख लाएगी, संतुष्टि लाएगी और सशक्त बनाएगी। आत्मनिर्भरता शब्द पिछले कुछ दशकों में भारत के शब्दकोष से गायब ही हो गया था। प्रधानमंत्री ने इसे सम्मान दिया है और एक बार फिर हमारे चिंतन में इसे स्थान दिया है।

कोरोनावायरस ने वैश्वीकरण को करारा झटका दिया है, उसकी कमियां उजागर कर दी हैं और स्पष्ट कर दिया है कि यदि भारत दुनिया में विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी आंतरिक शक्ति का निर्माण करना ही होगा। यह आत्मनिर्भरता से ही हो सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी सबको एकजुट करता था। उसने भारतीयों को औपनिवेशिक मालिकों के साथ लड़ाई के लिए एकजुट किया। हमें आत्मनिर्भरता के गांधीवादी मॉडल के मूल बिंदुओं पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इसमें टिकाऊ विकास, स्थानीय कौशल एवं संसाधनों के इस्तेमाल से स्थानीय उत्पादन शामिल है। कोरोनावायरस संकट ने मजबूत, विश्वास भरे और मिलकर काम करने वाले भारत के पुनर्निर्माण का जो मौका दिया है, उसे हम गंवा नहीं सकते। यह भारत अपने कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के कल्याण के लिए काम करता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी विदेश नीति और दुनिया के साथ जुड़ाव का स्तंभ बने, यह हमारी ही जिम्मेदारी है।

Source:

1.https://m.economictimes.com/hindi/news/atmanirbhar-bharat-abhiyan-do-you-know-these-important-facts/slideshow/75750176.cms
2.https://www.vifindia.org/article/hindi/2020/may/19/atamnirbharta-bharat-ke-punaruthan-ki-yojna
3.https://www.prsindia.org/hi/policy/report-summaries
4.https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Aatmanirbhar%20Presentation%20Part-1%20Business%20including%20MSMEs%2013-5-2020.pdf.
5.https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Aatma%20Nirbhar%20Bharat%20presentation%20Part-2%2014-5-2020.pdf.
6.https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Aatma%20Nirbhar%20Bharat%20Presentation%20Part-3%20Agriculture%2015-5-2020%20revised.pdf.
7.https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/AatmaNirbhar%20Bharat%20Full%20Presentation%20Part%204%2016-5-2020.pdf.
8.https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Aatma%20Nirbhar%20Bharat%20%20Presentation%20Part%205%2017-5-2020.pdf.

Kisan Shikshan Prasarak Mandal Borgaon (Kale) Tq. & Dist. Latur's

Vasantrao Kale Mahavidyalaya, Dhoki

Tq. & Dist. Osmanabad.(MS)

(NAAC 'B' Grade)

Organized by

Internal Quality Assurance Cell & Department of Economics

Organizes

One Day online National Conference in interdisciplinary subjects on

'Covid-19 Pandemic and its Impact on Socio-Economic Development in India'

Certificate

This is to certify that

Mr. / Mrs. YOGESHWAR SAHU

has attended / praper reading One Day online National Conference on 'Covid-19 Pandemic and its Impact on Socio-Economic Development in India' on 30th June, 2020 which was organized by Department of Economics, of our college. Hence certified.

Dr. Balasaheb Maind
H.O.D. Economice & Convener

Dr. Pradeep Ingale
IQAC Coordinator

Dr. Haridas Fere
Chief Organizer & Principal